11 -02-2023

उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV- D2

समाचार पत्रों में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SSLV- D2) का सफल प्रक्षेपण किया गया।

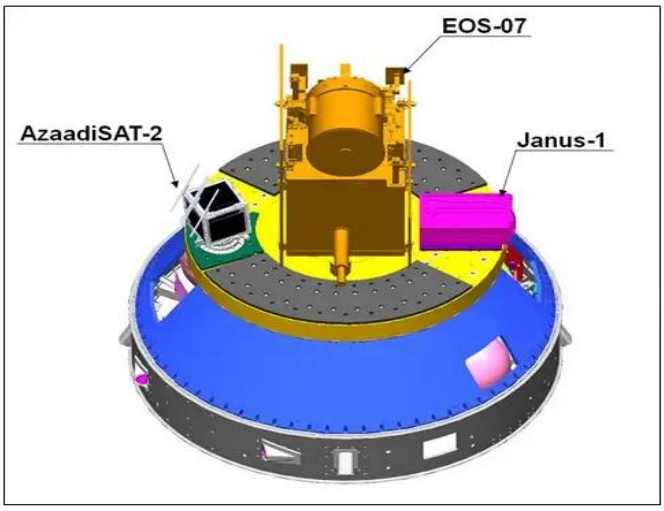

त्वरित मुद्दा?

- SSLV- D2 द्वारा इसरो के ईओएस-07, Janus-1 और आजादीसैट-2 उपग्रहों को गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- Janus-1 एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित Antaris और उसके भारतीय भागीदारों XDLinks और Ananth Technologies द्वारा बनाया गया है।
- आज़ादीसैट-2 को चेन्नई में स्पेस किड्ज़ इंडिया स्टार्ट-अप द्वारा निर्देशित भारत भर में लगभग 750 छात्राओं द्वारा विकसित किया गया है।
- EOS-07 को इसरो द्वारा डिजाइन, विकसित और निर्मित किया गया है।

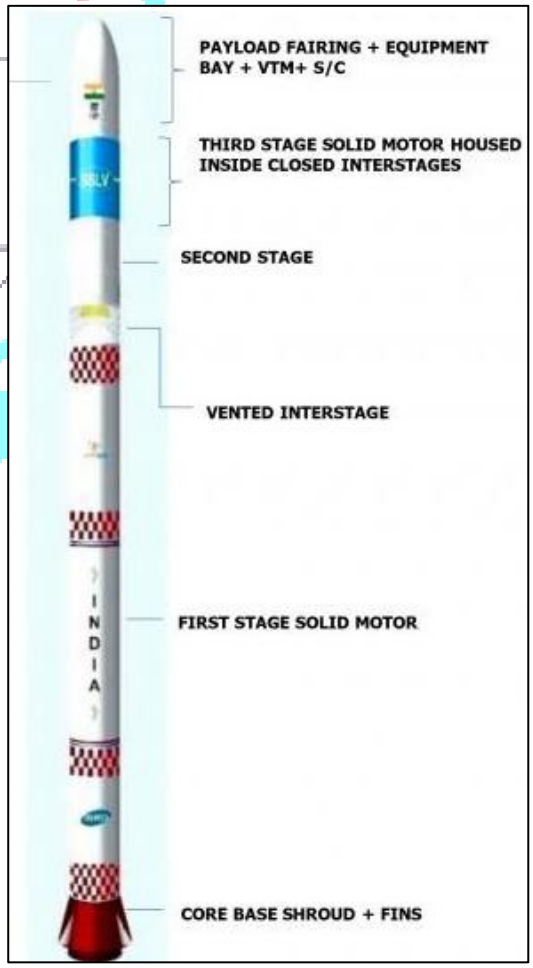

अन्य प्रमुख तथ्य?

एसएसएलवी की प्रमुख विशेषताएं

- कम लागत।
- कम टर्न-अराउंड समय।
- कई उपग्रहों को समायोजित करने का लचीलापन।
- लॉन्च-ऑन-डिमांड व्यवहार्यता।
- न्यूनतम लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताएं।

- इसका उद्देश्य भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक माइक्रोसेटेलाइट और नई तकनीकों के साथ संगत पेलोड उपकरणों को डिजाइन और विकसित करना है।

- एसएसएलवी 'लॉन्च-ऑन-डिमांड' के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है।
- लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (एसएसएलवी) एक 3 चरण का प्रक्षेपण यान है, जिसे टर्मिनल चरण के रूप में तीन ठोस प्रणोदन चरणों और तरल प्रणोदन आधारित वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल (वीटीएम) के साथ संरूपित किया गया है।
- यह एक 34 मीटर लंबा, 2 मीटर व्यास वाला रॉकेट है, जिसका उत्थापन द्रव्यमान 120 टन है।

श्री अन्न योजना

समाचार पत्रों में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना 5वां पूर्ण बजट पेश किया। इस बजट में उन्होंने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना की शुरुआत की चर्चा की है। आपको बता दें वित्त मंत्री ने मोटे अनाजों के लिए 'श्री अन्न' सम्बोधन का प्रयोग किया है।

त्वरित मुद्दा?

- वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा की, "भारत मोटे अनाजों यानि कि मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जायेगा। इसके अलावा मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट्स रिसर्च सेण्टर की भी स्थापना की जाएगी।"

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- श्री अन्न के अंतर्गत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू के दानों आदि को शामिल किया जाता है। ये अनाज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र ने भी भारत के प्रस्ताव पर साल 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया है।
- सरकार विशेष रूप से इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने मिलेट्स फ़ूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया था, जिसमें बहुत सारे मंत्रियों और सांसदों ने हिस्सा लिया था।
- जलवायु सहिष्णु - सबसे पहले तो ये अनाज जलवायु के प्रति सहिष्णु होते हैं और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन से आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन में भी कम लागत आती है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि पोषक तत्वों से भरपूर ये अनाज कम उर्वर और ऊसर मृदा में भी अच्छी उपज देते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये अनाज किसान के मित्र होते हैं जो कम लागत और कम परिश्रम में ही अच्छा उत्पादन करते हैं।
- कुपोषण के शत्रु- आज भुखमरी और कुपोषण भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में इन अनाजों को कुपोषण रोकने के एकमात्र उपाय के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें ये अनाज प्रोटीन, डायट्री फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज़, फॉस्फोरस, पोटैशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों का

खजाना होते हैं। भारत जैसे विशाल जनसँख्या वाले देशों के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन अनाजों को दैनिक भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

- बीमारियों से रखे दूर- मिलेट्स ग्लूटन फ्री और ग्लाइसीमिक इंडेक्स में लो होने के साथ ही साथ प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे ये डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और मोटापा कम करने में भी बहुत मददगार होते हैं।

अन्य प्रमुख तथ्य?

श्री अन्न योजना से होने वाले आर्थिक लाभ

- यूं तो मिलेट्स के फायदे ही फायदे हैं लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी। क्योंकि वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे जिससे देश में बेरोज़गारी भी कम होगी।

भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल

समाचार पत्रों में क्यों?

बजट की मेहरबानी इस बार लखनऊ के साथ-साथ मेरठ और गाज़ियाबाद की ट्रेन पर भी दिख रही है। दरअसल बीते एक फ़रवरी को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट प्रस्तुत किया। जिसमें दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच आने वाली भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के लिए 3,596 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

त्वरित मुद्दा?

- दरअसल दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस एक सेमी-हाई स्पीड रेल आधारित ट्रांजिट नेटवर्क है जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) कार्यान्वित कर रहा है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इसकी कुल लम्बाई 82 किलोमीटर है। जिसमें से 14 किमी दिल्ली में है जबकि 68 किमी उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करना है। साथ ही, वाहनों के आवागमन और वायु प्रदूषण को कम करेगा।

- इस परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया था। जून 2019 में इसका सिविल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। एक बार पूरी तरह से चालू हो जाने के बाद, आरआरटीएस ट्रेनों की डिजाइन स्पीड 180 किमी प्रति घंटा और ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी प्रति घंटा होगी।
- दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस से 55 मिनट के बीच दो प्रमुख शहरों के बीच की दूरी को कवर किया जा सकेगा और इस कॉरिडोर में कुल 25 स्टेशन होंगे। इस कॉरिडोर पर रैपिड रेल को 2025 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा।
- इसके एक कोच में 75 यात्री बैठकर सफर कर सकेंगे और अधिकतम 400 यात्री सफर कर सकेंगे। आपातकालीन स्थिति में रैपिड ट्रेन से मरीज को स्ट्रैचर पर अस्पताल ले जाया जा सकेगा।
- एनर्जी की बचत करने के लिए रैपिड रेल में जरूरत के आधार पर चुनिंदा दरवाजों को खोलने के लिए पुश बटन होंगे। जिससे हर स्टेशन पर सभी दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होगी।
- खास बात यह कि इस बार केंद्र सरकार के आम बजट में पिछली बार की तुलना में रेलवे को तकरीबन दोगुना बजट मिला है। जिसमे यूपी के खाते में और खास तौर से उत्तर मध्य रेलवे को एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है लेकिन बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने यूपी रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है।
- जैसे भाषण में यह कहा गया कि वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कोच रायबरेली में भी बनायें जायेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लखनऊ डिवीज़न के 44 स्टेशन सहित प्रदेश के अन्य स्टेशन को री-डेवलप्ड किये जायेंगे।

KAUTILYA ACADEMY INDORE